10 जून, 2016

राष्ट्रपति ओबामा की वियतनाम यात्रा

*डॉ. स्तुति बैनर्जी**

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वियतनाम का दौरा (23-25 मई 2016) किया। इस यात्रा को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले महत्व विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। एशियाई पुनः संतुलन रणनीति राष्ट्रपति की विस्तृत विदेश और आर्थिक नीति का एक केंद्रीय उद्देश्य रहा है, जिसमें यह विश्वास निहित है कि दुनिया में उभरता हुआ यह सबसे बड़ा बाजार अमेरिका की भविष्य की समृद्धि और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मेजबानों के हित लिए भी महत्वपूर्ण है।[1] इसका निर्माण राष्ट्रपति द्वारा अपनी विरासत पर करने और क्यूबा, ईरान, म्यांमार और अब वियतनाम जैसे पूर्व प्रतिद्वंद्वियों के साथ अमेरिका के संबंधों के पुनर्निर्माण की उनकी नीति को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है।

अमेरिका-वियतनाम संबंधों का इतिहास शीत युद्ध के प्रतिद्वंद्वियों और साम्यवाद की आशंकाओं में से एक है, जो एक ऐसा युद्ध है जिसमें अनगिनत लोग मारे गए, सैनिक अभी भी लापता हैं, अस्पष्टीकृत बारूदी सुरंगों व बमों और युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए रासायनिक एजेंटों के स्थायी प्रभाव अभी भी मौजूद हैं।

राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने विस्तृत 'पुनः संतुलन' के हिस्से के रूप में वियतनाम के साथ अमेरिका की बातचीत की रणनीतिक प्रकृति पर जोर देना था। यह उद्देश्य तब स्पष्ट हुआ जब राष्ट्रपति ने घोषणा की कि "...ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी), न केवल व्यापार का समर्थन करने हेतु बल्कि हमारे राष्ट्रों (अमेरिका और वियतनाम) को एक साथ लाने तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने हेतु...यह महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का समर्थन करेगा, आगे

वियतनाम को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करेगा, और अमेरिकी निर्यात पर वियतनाम के शुल्क को कम करेगा...." उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका "....वियतनाम को सैन्य उपकरणों की बिक्री से लगाये गए प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा रहा है, जो लगभग 50 वर्षों से जारी है। हमारे सभी (अमेरिका) रक्षा सहयोगियों के साथ, बिक्री के लिए अभी भी सख्त जरुरतों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित बातें शामिल हैं। लेकिन यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करेगा कि वियतनाम के पास वो उपकरण हो जिनकी उसे खुद की रक्षा करने और शीत युद्ध की भयावहता को खत्म करने हेतु आवश्यकता है। यह लंबे समय के लिए वियतनाम के साथ मजबूत रक्षा संबंध और इस क्षेत्र सहित वियतनाम के साथ पूरी तरह से सामान्यीकृत संबंधों के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।"[2]

संबंधों का पुनर्निर्माण

फ्रांसीसी संघ के भीतर अपनी सीमि त स्वतंत्रता के बाद , अमेरिका ने 1950 में वियतनाम के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हालाँकि , वियतनाम में गृहयुद्ध , शीत युद्ध की राजनीति और वियतनाम में अमेरिकी युद्ध के कारण, अमेरिका ने 1975 में अपने दूतावास को बंद कर दिया। यह 1995 में हुआ था जब अमेरिका ने वियतनाम के साथ संबंधों को औपचारिक रूप देने की घोषणा की। 2015 में दोनों राष्ट्रों ने वियतनाम युद्ध के अंत की 40वीं वर्षगांठ, राजनयिक संबंधों की 20वीं वर्षगांठ को राज्य के सचिव श्री जॉन केरी की वियतनाम और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी (वीसीपी) के महासचिव श्री गुयेन फु ट्रोंग की अमेरिका यात्राओं द्वारा चिह्नित किया गया।

2015 में महासचिव ट्रोंग का दौरा न केवल अपने महत्व में प्रतीकात्मक था , बल्कि अमेरिका-वियतनाम संबंधों में प्रमुख विकास भी था। श्री ट्रोंग की पांच दिवसीय यात्रा (6-10 जुलाई) के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति बराक ओबामा, उपराष्ट्रपति जो बिडेन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान राइस, राज्य सचिव केरी, राजकोष सचिव जैक ल्यू, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि माइकल फ्रोमैन , सेनेटर जॉन मैककेन और पैट्रिक लीह , अमेरिकी धार्मिक नेताओं , वियतनामी-अमेरिकी समुदाय के प्रतिनिधियों , अमेरिकी उद्यमियों, अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख , पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन , संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के समूह के साथ मुलाकात की। लोगों की श्रेणी और उनकी पृष्ठभूमि इस बात का संकेत है कि वियतनाम और अमेरिका व्यापक संबंधों की ओर देख रहे हैं। यह तब स्पष्ट हुआ जब 2015 में अमेरिका और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी हेतु आगे बढाया।

साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने हेतु एक व्यापक रूपरेखा है और एशिया-प्रशांत पुनःसंतुलन हेतु अमेरिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अमेरिकी-वियतनाम विस्तृत भागीदारी के अंतर्निहित सिद्धांतों में शामिल हैं ; संयुक्त राष्ट्र चार्टर , अंतर्राष्ट्रीय कानून और एक- दूसरे की राजनीतिक प्रणालियां, स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान। साझे दारी का उद्देश्य

प्रत्येक देश में , क्षेत्र और दुनिया में शांति , स्थिरता, सहयोग और समृद्धि में योगदान करना है। साझेदारी में राजनीतिक और राजनयिक संबंधों, व्यापार और आर्थिक संबंधों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और प्रशिक्षण , पर्यावरण और स्वास्थ्य , युद्ध विरासत के मुद्दों , रक्षा और सुरक्षा , मानव अधिकारों, और संस्कृति, खेल और पर्यटन का संरक्षण और संवर्धन सहित क्षेत्रों में सहयोग शामिल था।[3]

यहाँ तक की साझेदारी की घोषणा से पहले ही अमेरिका और वियतनाम ने पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध बनाने हेतु कदम उठाए थे। दो नों देश कई क्षेत्रीय संगठनों जैसे कि आसियान और एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम और संयुक्त राष्ट्र , आईएमएफ, विश्व बैंक , आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य हैं। क्षेत्र में शांति , स्थिरता, सहयोग और समृद्धि बढ़ाने हेतु दोनों देश अब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 2001 में अमेरिका-वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लागू होने के बाद से दोनों के बीच आर्थिक संबंध लगातार अच्छे हुए हैं। अमेरिका- वियतनाम द्विपक्षीय व्यापार 1995 में 451 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2014 में लगभग $35 बिलियन डॉलर हो गया है।[4] दोनों देशों की प्राथमिकता टीपीपी और इसके प्रस्तावित लाभ हैं।

इस संबंध के प्रमुख पहलुओं में से एक, यदि संभव हो तो, वियतनाम (इंडोचाइना) में लापता या गुम हुए सैनिकों का पता लगाना और उनका प्रत्यावर्तन है। संयुक्त पीओडब्ल्यू/एमआईए लेखा कमान वियतनाम में प्रति वर्ष चार प्रमुख जांच एवं पुनर्प्राप्ति समय का आयोजन करता है, जिसके दौरान विशेष रूप से प्रशिक्षित अमेरिकी सैन्य तथा सिविल कर्मी जांच और पूर्ण संभवित प्रत्यावर्तन की खोज में सैकड़ों मामलों की जांच करते हैं। अगस्त 2011 के बाद से इन पुनर्प्राप्ति अभियानों में वियतनामी के नेतृत्व वाली रिकवरी टीम नियमित रूप से भागीदार बन गई है। अभी भी लगभग 1600 सैनिक हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया (लाओस, कंबोडिया, आदि) में अपने मोर्चों से अमेरिकी सशस्त्र बलों के अनुसार लापता हैं, इनमें से लगभग 1300 लापता सैनिक वियतनाम में हैं।[5] अमेरिकी सरकार का प्रयास जितना संभव हो उतने सैनिकों का पता लगाना सुनिश्चित करना है।

अन्य प्रमुख बिंदु जो दोनों के बीच रक्षा सहयोग की नींव हैं, वे अस्पष्टीकृत अध्यादेश (यूएक्सओ) की पुनप्राप्ति और नष्ट करने में अमेरिकी सहायता हैं। वियतनाम युद्ध के विस्फोटक अवशेषों से भारी प्रदूषण हुआ है, जिसमें क्लस्टर मूनिशन द्वारा व्यापक संदूषण शामिल है। जैसा कि होना चाहिए, अमेरिका वियतनाम में यूएक्सओ/खनन कार्यों में सबसे बड़ा एकल दाता है, और दोनों देशों ने दिसंबर 2013 में जारी अस्पष्टीकृत अध्यादेश सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2007 से (2015 तक) अमेरिकी कांग्रेस द्वारा वियतनाम युद्ध के दौरान देश के दक्षिणी भागों में एजेंट ऑरेंज में निहित डाइऑक्सिन और तृणनाशक छिड़काव से पर्यावरणीय और स्वास्थ्य क्षति की समस्या को दूर करने के लिए 130 मिलियन डॉलर से अधिक का विनियोजन किया गया है। हाल के वर्षों में, वियतनाम में एजेंट ऑरेंज और इससे जुड़े डाइऑक्सिन के कारण पर्यावरणीय क्षति और स्वास्थ्य

समस्याओं पर अमेरिका की प्रतिक्रिया को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद के रूप में देखा गया है।[6]

वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान, महासचिव ट्रोंग ने व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात की, जो एक सम्मान था जो सामान्य रूप से राज्य या सरकार के प्रमुखों के लिए आरक्षित है। यह सम्मान इस महत्व का प्रतीक था कि अमेरिका संबंधों में वियतनाम की राजनीतिक प्रणाली में महासचिव की प्रमुख स्थिति को स्वीकार करता है और उसके प्रति अमेरिका सम्मान प्रदर्शित करता है। अमेरिका "एक दूसरे की राजनीतिक प्रणालियों, स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान के आधार पर गहरा, सतत, और मजबूत संबंध बनाने के लिए सहमत हुआ।" दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक ने वियतनाम के नेताओं की भविष्य की यात्राओं के लिए एक उदाहरण कायम किया। वियतनाम की यात्रा ने इस आशंका को दूर करने में मदद की कि अमेरिका वियतनाम में शांतिपूर्ण शासन के माध्यम से उनके शासन के रूप को बदल देना चाहता है और राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकता है।[7]

राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा

राष्ट्रपति की यात्रा विशेष रूप से अपनी एशियाई पुनःसंतुलन नीति को आगे बढ़ाने हेतु साझेदारी बनाने के प्रयासों में वियतनाम के प्रति अमेरिका के महत्व को दोहराती है। भौगोलिक मध्य बिंदु पर स्थित, पूर्वोत्तर एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले वियतनाम में 2000 मील का समुद्र तट है जो दक्षिण चीन सागर की ओर सम्मुख है। यह जीवंत अर्थव्यवस्था का निवास है और आसियान के साथ इसके जुड़ाव ने इसे क्षेत्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है।[8] क्योंकि अमेरिका एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, ऐसे में वियतनाम के साथ अच्छे संबंधों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है।

'खराब मानवाधिकारों रिकॉर्ड' के बावजूद हथियारों पर से प्रतिबंध हटाने को स्पष्ट रूप से अमेरिकी पुनःसंतुलन नीति से जोड़ा गया है। अमेरिका ने कहा है कि एशियाई देशों के साथ गहरे और व्यापक संबंधों की नीति का आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा आयाम है। वियतनाम को हथियारों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाना इस बड़ी रणनीति का हिस्सा है। प्रेस के साथ अपनी बातचीत में, राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि, "... प्रतिबंध को हटाने का निर्णय चीन या किसी अन्य विचार पर आधारित नहीं था।"[9] हालांकि, यह स्वीकार करना कि अमेरिका का यह फैसला आंशिक रूप से चीन पर आधारित नहीं है, सरल होगा। राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी टिप्पणी में कहा, "... संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम एक क्षेत्रीय क्रम में हमारे समर्थन में एकजुट हुए हैं, जिसमें दक्षिणी चीन सागर भी शामिल है - जहां अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और नियमों को बरकरार रखा जाता है, जहां नेविगेशन और उड़ान पर स्वतंत्रता है, जहां वैध वाणिज्य को बाधित नहीं किया जाता है, और जहां अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार, कानूनी तरीकों के माध्यम से विवादों को शांति से हल किया जाता है।" उन्होंने आगे कहा,

"... जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून अनुमति देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका उड़ान, जलयात्रा और संचालन करना जारी रखेगा, और हम सभी देशों को ऐसा करने के अधिकार का समर्थन करेंगे।"[10] ब्रुनेई को छोड़कर, अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर विवाद को लेकर सभी देशों की पार्टियों के साथ घनिष्ठ साझेदारी स्थापित की है।[11]

प्रतिबंध हटाने का निर्णय भी (तत्कालीन) रक्षा सचिव श्री लियोन पेनेटा द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों को जारी रखने के लिए किया गया है, जो कि अमेरिकी आपूर्ति जहाजों की कैम रान्ह बे तक पहुंच और इसकी मरम्मत सुविधाओं की अनुमति देता है। अमेरिका उच्च स्तरीय आदान-प्रदान, समुद्री क्षेत्र में, खोज और बचाव में, मानवीय सहायता और आपदा राहत और शांति अभियानों में विकास चाहता है।[12] इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने हथियार हस्तांतरण का उपयोग कर न केवल प्वाइंट ऑफ-सेल बिक्री अर्जित किया बल्कि सुरक्षा सहयोग के चल रहे संबंधों को स्थापित करने का भी प्रयास किया है, इसमें स्पेयर पार्ट्स की बिक्री और मरम्मत दोनों के साथ-साथ शैक्षिक आदान-प्रदान, प्रशिक्षण और अभ्यास के अवसर शामिल हैं। हालांकि, संबंध सीमित बिक्री के साथ शुरू हो सकते हैं, लेकिन यह समय के साथ अधिक व्यापक रक्षा संबंध का कारण बन सकते हैं।[13] वियतनाम अमेरिका के ग्लोबल पीस ऑपरेशंस पहल का भागीदार है।[14] 2014 में, इसने छोटे तरीके से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान देना शुरू किया, लेकिन निकट भविष्य में इंजीनियरिंग, चिकित्सा और अन्य विशिष्ट इकाइयों को भेजने की योजना के साथ, जिसमें अमेरिका उन कर्मियों को प्रदान करने पर सहमत हुआ जो वियतनामी सेनाओं के प्रशिक्षण में सहायता कर सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर 2016 अमेरिका द्वारा वियतनाम को स्थायी सामान्य व्यापार संबंधों (पीएनटीआर) स्थिति देने की 15वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित है। [अमेरिका और वियतनाम ने 13 जुलाई 2000 को एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो 10 दिसंबर, 2001 को लागू हुआ। बीटीए के हिस्से के रुप में अमेरिका ने वियतनाम को सशर्त सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) व्यापार का दर्जा दिया, जो अब सामान्य व्यापार संबंधों (एनटीआर) के रूप में जाना जाता है।] फरवरी 2016 में भी दोनों देशों ने टीपीपी पर हस्ताक्षर किए थे। 2011 से, अमेरिकी कांग्रेस ने वियतनाम के आर्थिक सुधारों का समर्थन करने हेतु प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन डॉलर से अधिक का विनियोजन किया है। इसके अलावा, दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) और डब्ल्यूटीओ समझौतों के कार्यान्वयन के साथ-साथ सामान्य रूप से व्यापार और निवेश नीतियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु मंत्री-स्तरीय व्यापार और निवेश समझौता (टीआईएफए) परिषद की स्थापना की है।[15] अमेरिका-वियतनाम माल व्यापार 1995 में 451 मिलियन डॉलर का था, जिस वर्ष अमेरिका और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंध सामान्य हुए, जो आज 45 बिलियन डॉलर के करीब है।[16]

राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने टीपीपी का अनुसमर्थन करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। टीपीपी में शामिल होने का वियतनाम का प्रोत्साहन बड़े पैमाने पर विशेष रूप से कृषि सामानो, एक्वा-सांस्कृतिक सामानों, कपड़े और जूतों के लिए अमेरिकी बाजार की पहुंच पर निर्भर है। अमेरिका के लिए, वियतनाम अमेरिकी निर्यात हेतु एक महत्वपूर्ण बाजार प्रदान करता है, लेकिन कुछ दल वियतनाम के श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य-नियंत्रित उद्यमों से संभावित अनुचित प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित हैं।[17] अमेरिका ने वियतनाम को श्रम, पर्यावरण और बौद्धिक संपदा अधिकारों के मानक को पूरा करने हेतु तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश की है जो टीपीपी का हिस्सा हैं। बदले में, वियतनाम को श्रम सुधारों को लागू करना है। राष्ट्रपति क्वांग ने कहा कि, "टीपीपी एक महत्वपूर्ण व्यापार और आर्थिक संबंध है।... टीपीपी और वियतनाम की टीपीपी में भागीदारी व्यापक अंतरराष्ट्रीय एकीकरण की हमारी (वियतनाम की) प्रक्रिया में वियतनामी सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है।"[18] अमेरिका के लिए, टीपीपी आर्थिक और रणनीतिक रूप से लाभकारी है। समझौते से अमेरिका को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार हेतु कानूनी ढांचा तैयार करने और तेजी से आर्थिक विकास कर रहे क्षेत्र पर अपने प्रभाव को मजबूत करने की अनुमति मिलती है। जैसा कि टीपीपी के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने अपने बयान में कहा था, "टीपीपी अमेरिका को न की चीन जैसे देशों को अनुमति देता है - कि वें 21वीं शताब्दी के भविष्य के नियमों को लिखें।...." अमेरिका आसियान आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा कनेक्टिविटी के विकास में सहायता करने और सतत, नवाचार-आधारित आर्थिक विकास का इच्छुक है। इस संबंध में वह अमेरिका-आसियान कनेक्ट पहल के माध्यम से वियतनाम के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना चाहता है।[19]

अमेरिका और वियतनाम ने अप्रैल 2016 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राष्ट्रों ने परमाणु सुरक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा उपायों और अप्रसार सहित कई क्षेत्रों में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में जुड़ाव समेत 123 समझौते के कार्यान्वयन की सुविधा और साथ ही सहयोग और सूचना के साझाकरण के लिए असैन्य परमाणु सहयोग पर अमेरिका-वियतनाम संयुक्त समिति की घोषणा की। भविष्य में यह सौदा अमेरिकी परमाणु उद्योग के लिए फायदेमंद साबित होना चाहिए और संवेदनशील और/या दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान/बिक्री पर भविष्य के सौदे का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है।

वियतनाम में मानव अधिकार का मुद्दा दोनों देशों के बीच असहमति का विषय रहा है लेकिन इसे इस संबंध की मजबूती को कम करने हेतु किसी बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर विषय शामिल हैं। अप्रैल 2016 में, अमेरिका-वियतनाम मानवाधिकार वार्ता का 20वां

सत्र वाशिंगटन, डीसी में आयोजित किया गया था। वार्षिक कार्यक्रम वियतनाम मे कानूनी सुधार के प्रयासों, कानून के शासन, अभिव्यक्ति और जनसमूह की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, श्रम अधिकारों, विकलांगता अधिकार, एलजीबीटीआई अधिकार, बहुपक्षीय सहयोग, साथ ही साथ चिंता के व्यक्तिगत मामले की प्रगति पर केंद्रित है। निकट भविष्य के लिए अमेरिका राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जो कि टीपीपी के हिस्से के रूप में वियतनामी संविधार, श्रमिक अधिकार और आर्थिक उदारीकरण में निहित है और व्यवहार्यता एवं पारदर्शिता की दिशा में वियतनामी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुमोदन करते हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने वियतनाम के लोगों को अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि जहां दोनों देशों के इन मुद्दों पर मतभेद हैं, वहीं अमेरिका वियतनाम पर अपने विचार को नहीं थोपेगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम इन अधिकारों को अमेरिका की तुलना में अलग तरह से लागू करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश इन मुद्दों पर काम करेंगे और उन पर सुधार करेंगे।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति ओबामा और महासचिव ट्रोंग के बीच बैठक से ऐसी नींव रखी गई है, जिस पर अमेरिका और वियतनाम अपने भविष्य के रिश्ते का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा की यात्रा आंशिक रूप से पारस्परिक और आंशिक रुप से अमेरिका की एशिया रणनीति को मजबूत करने वाली थी, जिसमें क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ बेहतर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध शामिल थे। इस नीति का महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढ़ाना है। अमेरिका को उम्मीद है कि वियतनाम के साथ अच्छे संबंध उसे देश में भविष्य के आर्थिक और राजनीतिक सुधारों को प्रोत्साहित करने की सुविधा देंगे। वियतनाम के लिए, अमेरिका के साथ संबंध विकास के मुद्दों और पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की उसकी क्षमता को बढ़ा देगा। यह वियतनाम को उसकी क्षेत्रीय स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

दोनों देशों के बीच द्वि-पक्षीय संबंध भविष्य के लिए आशाजनक हैं। वाशिंगटन और हनोई दोनों के इस क्षेत्र में समान हित हैं और हितों का यह झुकाव दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है, जो दोनों राष्ट्रों के बीच मतभेदों को सुलझाने की क्षमता रखता है।

***

**डॉ. स्तुति बैनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली के साथ शोध अध्येता हैं।*
अस्वीकरण: व्यक्त किए गए विचार शोधकर्ता के हैं और ये परिषद के विचार को नहीं दर्शाते हैं।

अंत टिप्पण:

---

[1] Office of the Press Secretary, The White House, "Press Call on the Upcoming Trip to Vietnam and Japan", https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/20/press-call-upcoming-trip-vietnam-and-japan, (accessed on 01 June 2016).

[2] The Office of the Press Secretary, The White House, "Remarks by President Obama and President Quang of Vietnam in Joint Press Conference," https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/23/remarks-president-obama-and-president-quang-vietnam-joint-press, (accessed on 01 June 2016).

[3] The Office of the Press Secretary, The White House, "Joint Statement by President Barack Obama of the United States of America and President Truong Tan Sang of the Socialist Republic of Vietnam,", https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/25/joint-statement-president-barack-obama-united-states-america-and-preside, (accessed on 07 June 2016).

[4] The US Embassy in Vietnam, "U.S. - Vietnam Relations," http://vietnam.usembassy.gov/usvnrelations.html (accessed on 02 June 2016).

[5] Details are available at Defence POW/MIA Accounting Agency

[6] Michael F. Martin (a), "U.S. Agent Orange/Dioxin Assistance to Vietnam," https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44268.pdf, (accessed on 02 June 2016).

[7] Carl Thayer, "8 Developments in US-Vietnam Relations Show Emerging Partnership", The Diplomate, July 13, 2015, http://thediplomat.com/2015/07/8-developments-in-us-vietnam-relations-show-emerging-partnership/, (accessed on 02 June 2016).

[8] Murray Hiebert, Phuong Nguyen and Gregory B. Poling, "A New Ear in US-Vietnam Relations: Deepening Ties Two Decades after Normalisation," https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/140609_Hiebert_USVietnamRelations_Web.pdf, (accessed on 06 June 2016).

[9] Op. Cit. 6, Michael F. Martin (a)

[10] Ibid.

[11] The parties to the dispute apart from China are Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, Indonesia, and the Philippines.

[12] US Department of Defence, "Panetta's Cam Ranh Bay Visit Symbolizes Growing U.S.-Vietnam Ties," http://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=116597, (accessed on 01 June 2016).

[13] Scott W. Harold, "Why has Obama Lifted the Arms Sales Ban on Vietnam?," http://www.newsweek.com/why-has-obama-lifted-arms-sales-ban-vietnam-463435, (accessed on 01 June 2016).

[14] Global Peace Operations Initiative is a US Government-funded security assistance program intended to enhance international capacity to effectively conduct United Nations and regional peace support operations (PSOs) by building partner country capabilities to train and sustain peacekeeping proficiencies; increasing the

number of capable military troops and formed police units (FPUs) available for deployment; and facilitating the preparation, logistical support, and deployment of military units and FPUs to PSOs. More information is available at http://www.state.gov/t/pm/ppa/gpoi/

[15] Michael F. Martin (b), "U.S.-Vietnam Economic and Trade Relations: Issues for the 114th Congress," https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41550.pdf, (accessed on 07 June 2016).

[16] The Office of the Press Secretary, The White House, "FACT SHEET: Trade and Investment with Vietnam," https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/24/fact-sheet-trade-and-investment-vietnam, (accessed on 07 June 2016).

[17] Op Cit 15 Michael F. Martin (b).5

[18] Office of the Press Secretary, The White House, "Remarks by President Obama and President Quang of Vietnam in Joint Press Conference," https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/23/remarks-president-obama-and-president-quang-vietnam-joint-press, (accessed on 01 June 2016).

[19] U.S.-ASEAN Connect announced by President Obama at the U.S.-ASEAN Summit in Sunnylands, CA, (Feb. 2016) will strengthen the United States economic engagement with the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the ASEAN Member States (AMS). Strong economic ties are at the core of the United States and ASEAN's decades-long partnership.